



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042025-262580
CG-DL-E-21042025-262580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1772]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2025/वैशाख 1, 1947

No. 1772]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2025/VAISAKHA 1, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

का.आ. 1805(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायकी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए विविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाता है:

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय कहा गया है) ई-नाम का प्रशासन कर रहा है, जिसका उद्देश्य बाजारों को एकीकृत करके और राज्यों के भीतर अंतर-मंडी और अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देकर ई-नाम का विस्तार और समेकन करना है; ई-नाम के माध्यम से वेयरहाउस आधारित बिक्री (डब्ल्यूबीएस) और ईएनडब्ल्यूआर ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करना; किसानों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को लाभ प्रदान करने के लिए नए मॉड्यूल को सक्रियता से औपचारिक रूप देना; कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) या विनियमित बाजार समिति (आरएमसी) मंडियों से इतर ई-नाम मंच खोलना जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित हो; अंतर-मंडी और अंतर-राज्यीय ई-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रणालियों को मजबूत करना और ट्रेड रिलायबल ग्रेड मानक विकसित करना; और बाजार में अधिक मांग पैदा करने और किसानों को लाभान्वित करने हेतु प्राथमिक

व्यापार के साथ-साथ द्वितीयक व्यापार भी ई-नाम (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाद उक्त स्कीम कहा गया है) के माध्यम से किया जाएगा:

उक्त स्कीम के अधीन संबंधित उपस्कर या बुनियादी ढांचे के लिए प्रति मंडी ₹75.00 लाख की सीमा के अधीन एकमुश्त निर्धारित लागत जिसमें प्रारंभ में कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट सुविधा, परीक्षण उपस्कर के लिए प्रति मंडी ₹30.00 लाख एकमुश्त निर्धारित अनुदान के रूप में आवंटित किए जाते हैं, जबकि छंटाई, ग्रेडिंग, सफाई और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं के सृजन के लिए प्रति मंडी अतिरिक्त ₹ 40.00 लाख मंजूर किए जाते हैं और किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभार्थी कहा गया है) को प्रति मंडी बायो कम्पोस्ट यूनिट के लिए ₹5.00 लाख (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ कहा गया है) प्रदान किए जाते हैं तथा इसके संबंध में अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

उक्त स्कीम के लिए भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है:

यह मंत्रालय उक्त लाभ की प्राप्ति की शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ यह अपेक्षा करता है कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुजरे, या आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करे, या ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे आधार संख्या नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे:

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों), प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित समनुदेशित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा अथवा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त मंत्रालय ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी नामांकन होना है, या रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करने या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा:

जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या समनुदेशित नहीं कर दी जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके, जिनके लिए वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, या यदि उक्त मंत्रालय द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदत्त या अधिकृत सॉफ्टवेयर उन दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव का निष्पादन करने वाले अधिकारियों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना को प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, अर्थात्:—

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए, जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने की पावती, जिसमें ईआईडी सम्मिलित है; और

(ख) लाभार्थी की तस्वीर वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्: -

- (i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
 - (ii) राशन कार्ड;
 - (iii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे की पंक्ति का न हो;
 - (iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
 - (v) भारतीय पासपोर्ट;
 - (vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक पत्र;
 - (vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
 - (viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यंगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यंगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;
 - (ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;
 - (x) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि को निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र;
- या
- (xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
 - (I) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;
 - (II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
 - (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
 - (IV) यदि वह भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से विभिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा; या
 - (xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता को प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य

अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम 1999 या दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज जो उक्त मंत्रालय निर्दिष्ट करे

(4) इस संबंध में उक्त मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी के संबंध में जांच करेगा, -

(क) ईआईडी को माई आधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की यह करने के लिए कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) अन्य दस्तावेज और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी इकाई या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों को सुविधाजनक रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जहां किसी लाभार्थी की आधार संख्या का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे के प्रतिबिम्ब, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, किसी भी कारण से विफल हो जाता है जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त स्कीम के अधीन लाभ, यथास्थिति आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसके आधार नंबर के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का सुलभ उपयोग करके) सम्मिलित है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

- (ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से या इसके एमआधार ऐप का सुलभ उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है) यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात सम्मिलित है।

4. उक्त में इसमें किसी भी बात के होते हुए भी, -

(क) जहां पैरा 1 के खंड (3) के अधीन लाभ दिया जाता है, उसके संबंध में एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 22016/19/2015एम.॥Vo॥पीटी1-भाग(2) एफटीएस-144098]

पूर्ण चंद्र किशन, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2025

S.O. 1805(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the said Ministry) is administering e-NAM with an objective to expand and consolidate the e-NAM through integrating markets and promoting inter-mandi within State and inter-state trade; to focus on Warehouses Based Sale (WBS) and eNWR trade through e-NAM; to proactively formalize new modules to provide benefits to the farmers and Farmer Producer Organisations (FPOs); to open the e-NAM platform beyond Agricultural Produce Market Committee (APMC) or Regulated Market Committees (RMC) mandis to create further competition and ensure competitive price realisation to the farmers; to strengthen quality assaying systems and to develop trade reliable grade standards to promote inter-mandi and inter-State e- trade; and to create further demand in market and to benefit farmers, along with the primary trade, secondary trade will also be undertaken through e-NAM (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas one-time fixed cost subject to the ceiling of ₹ 75.00 lakhs per Mandi for related equipment or infrastructure, initially ₹ 30.00 lakhs per mandi is allotted as one-time fixed grant for computer hardware, internet facility, assaying equipment, while additional ₹ 40.00 lakhs per mandi is sanctioned for creation of facilities such as sorting, grading, cleaning and packaging and for bio composting unit per mandi ₹ 5.00 lakhs (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Farmers and Farmer Producer Organisations (FPOs) (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India:

And whereas the said Ministry is desirous, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Ministry shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said **Ministry** for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
 - (ix) Driving licence issued in India;
 - (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (xi) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of

Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) Any other document as the said **Ministry** may specify:

(4) An officer designated by the said **Ministry** in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

- (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
- (b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

- (a) where benefit is given under clause (3) of paragraph 1, a record shall be maintained in respect of the same, where shall be reviewed and audited periodically by the **Ministry**.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the **Ministry** shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 22016/19/2015M.IIVolVpt1-Part(2) FTS-144098]

PURNA CHANDRA KISHAN, Jt. Secy. (Marketing)